शोध मंथन Vol. XVII No.2 Apr.- June. 2026 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *https://anubooks.com/journal-volume/shodhmanthan-vol-xvii-june-2026-no2*

भारत में वामपंथी उग्रवाद–वैचारिक द्वंद्व, रणनीतिक विस्तार और पूर्ण अवसान का विश्लेषण

प्राप्तिः 28.05.2026
स्वीकृतः 19.06.2026

55

श्री प्रभाकर
एम. ए. (नेट), राजनीति शास्त्र
ईमेलः *prabhakarved@gmail.com*

सारांश

भारत में नक्सलवाद का उदय केवल एक कानून–व्यवस्था की समस्या नहीं थी, बल्कि यह स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त आर्थिक असमानता और भूमि सुधारों की विफलता का परिणाम था। इस आंदोलन ने माओवादी सिद्धांतों के आधार पर 'सशस्त्र क्रांति' का मार्ग चुना, जिसका प्रभाव देश के कई राज्यों में श्लाल गलियारेश (Red Corridor) के रूप में देखा गयाप् पूर्व के विश्लेषण के अनुसार, इस विद्रोह में वे वर्ग अधिक सक्रिय हुए जो सामाजिक भेदभाव और शोषण का शिकार थे। बीते कुछ दशकों में सरकार ने एक व्यापक रणनीति अपनाई, जिसमें 'कोबरा' और 'ग्रेहाउंड्स' जैसे प्रशिक्षित बलों के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित की गई और 'रोशनी' जैसी योजनाओं के जरिए कौशल विकास को बढ़ावा दिया गया। वर्तमान में, विकास की बढ़ती पहुंच और सुरक्षा बलों के निरंतर दबाव के कारण यह हिंसक विचारधारा अपने अंतिम चरण में है।

मुख्य शब्द

नक्सलवाद, माओवादी विचारधारा, आर्थिक विषमता, लाल गलियारा, अवसान, गोरिल्ला युद्ध,सामाजिक न्याय।

प्रस्तावनाः आंतरिक सुरक्षा का एक ऐतिहासिक संकट

भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख नक्सलवाद एक ऐसी भयावह चुनौती बनकर उभरा जिसने राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा की नींव को हिलाने का प्रयास किया। इसकी जड़ें केवल हिंसा में नहीं, बल्कि गहरे सामाजिक–आर्थिक भेदभाव और विकास की असमानता में निहित थीं। 'द हिंदू' (संपादकीय, 12 मार्च 2021) के एक विश्लेषण के अनुसार, नक्सलवाद का उदय प्रशासनिक तंत्र की उन क्षेत्रों तक पहुँच न हो पाने का परिणाम था जहाँ आदिवासियों और गरीबों का शोषण चरम पर था। नक्सलवाद भारत के लिए एक विकट समस्या का रूप धारण कर चुका था, जिसकी शुरुआत 1967 के किसान विद्रोह से हुई।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i02.055

वैचारिक अधिष्ठानः मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद का संगम

नक्सलवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से विदेशी साम्यवादी दर्शन पर आधारित है। मार्क्सवादी वर्ग संघर्षः कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों ने समाज को दो वर्गों–शोषक और शोषित में विभाजित देखा, जिससे विद्रोहियों को वैचारिक आधार मिला। माओवादी रणनीतिः चीनी क्रांति के प्रणेता माओत्से तुंग के विचार, विशेषकर ''सत्ता बंदूक की नली से निकलती है'', इस आंदोलन का मूल मंत्र बने। कोई भी विचार शून्य के गर्भ से उत्पन्न नहीं होताय नक्सलवाद का उदय भी तत्कालीन परिस्थितियों और आर्थिक विषमता का परिणाम था।

'रक्त–रंजित गलियारा' (Red Corridor) एवं उग्रवाद का क्षेत्रीय प्रसार

भारतीय गणराज्य की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष नक्सलवाद एक ऐसी विकट चुनौती बनकर उभरा, जिसने राष्ट्र की अखंडता को खंडित करने का कुत्सित प्रयास किया। इस आंदोलन का भौगोलिक विस्तार 'लाल गलियारे' के रूप में परिलक्षित हुआ, जिसकी बिंदुवार विवेचना अधोलिखित हैः

1. उद्गम एवं प्रारंभिक प्रादुर्भावः पश्चिम बंगाल के एक लघु ग्राम 'नक्सलबाड़ी' से प्रस्फुटित यह कृषक विद्रोह शनैः–शनैः एक सुसंगठित राजसत्ता–विरोधी आंदोलन में परिवर्तित हो गया। 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' (फरवरी 2026) के एक लेख के अनुसार, ''नक्सलबाड़ी मात्र एक भौगोलिक स्थान नहीं, अपितु एक ऐसी हिंसक विचारधारा का केंद्र बना जिसने दशकों तक भारतीय वनों को रक्तरंजित किया''।

2. विस्तृत भौगोलिक व्याप्तिः इस उग्रवादी विचारधारा का प्रभाव केवल एक राज्य तक सीमित न रहकर आंध्र प्रदेश (वर्तमान तेलंगाना), बिहार, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं केरल के सुदूर अंचलों तक विस्तृत हो गया। उत्तर प्रदेश का पूर्वी प्रक्षेत्र एवं उत्तराखंड के सीमावर्ती जनपद भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहे।

3. जनपदों का व्यापक संजालः गृह मंत्रालय के प्रतिवेदनों के अनुसार, राष्ट्र के लगभग चार दर्जन से अधिक जनपद इस हिंसा से भीषण रूप से प्रभावित रहे हैं। 'द हिंदू' (संपादकीय, 12 मार्च 2021) ने उल्लेख किया कि नक्सलवाद का विस्तार उन क्षेत्रों में अधिक सघन रहा जहाँ प्रशासनिक पैठ और विकास की किरणें न्यूनतम थीं।

4. उग्रवाद के केंद्र का अभ्युदयः छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का प्रादुर्भाव नक्सलवाद के एक प्रमुख केंद्र के रूप में हुआ, जिसे प्रायः विद्रोहियों की श्राजधानीश की संज्ञा दी गई। यहाँ का 'दंडकारण्य' क्षेत्र पूर्णतः नक्सली अधिनियतों एवं उनके निरंकुश प्रभाव के अधीन आ गया।

5. समांतर शासन की स्थापनाः इन प्रभावित क्षेत्रों में विद्रोहियों ने भारतीय प्रशासन के विरुद्ध अपनी 'समांतर सरकार' स्थापित की, जिसे 'जनत सरकार' के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ के सामान्य जनजीवन से लेकर समस्त आर्थिक गतिविधियों पर इन उग्रवादियों का व्यापक नियंत्रण स्थापित हो गया।

6. संगठनात्मक सुदृढ़ीकरणः अस्सी के दशक में कोनापल्ली सीतारामैया द्वारा 'पीपुल्स वार ग्रुप' की स्थापना ने इस गलियारे को और अधिक हिंसक एवं भयावह बना दिया। 'द इंडियन एक्सप्रेस' (जनवरी 2026) की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार, ''वर्ष 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप एवं एम.

सी.सी. के विलय ने एक अत्यंत शक्तिशाली उग्रवादी सैन्य बल को जन्म दिया, जिसने सुरक्षा बलों के समक्ष अभूतपूर्व चुनौतियां प्रस्तुत कीं।''

7. रणनीतिक लक्ष्य एवं अखंडताः विद्रोहियों की योजना भारत की सीमाओं के भीतर ही नहीं, अपितु नेपाल से लेकर दंडकारण्य एवं आंध्र प्रदेश तक एक अखंड 'क्रांतिकारी गलियारा' विकसित करने की थी। इसका मुख्य प्रयोजन एक ऐसा निरापद मार्ग निर्मित करना था जहाँ से शस्त्रास्त्रों एवं रसद की आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जा सके।

8. संसाधनों का हिंसक संग्रहणः इस विस्तृत भू–भाग में अपने वर्चस्व को अक्षुण बनाए रखने के लिए विद्रोहियों ने भू–स्वामियों, राजनीतिज्ञों एवं धनिक वर्ग से बलपूर्वक धन–उगाही, लूटपाट एवं अपहरण जैसे जघन्य साधनों का आश्रय लिया। 'दैनिक जागरण' (अक्टूबर 2025) के एक लेख में स्पष्ट किया गया है कि ''धन और संसाधनों के लिए नक्सलियों द्वारा किया गया शोषण ही अंततः उनके सामाजिक आधार के पतन का कारण बना।''

संगठनात्मक ढांचा और गुरिल्ला युद्धनीति

नक्सलियों ने एक अत्यंत जटिल और अनुशासित ढांचा तैयार किया है।

केंद्रीय समितिः यह समिति संगठन का 'मस्तिष्क' कहलाती है, जो पूरे आंदोलन का संचालन करती है। सैन्य दल (दलम)ः ये दल छापामार या गोरिल्ला युद्ध में निपुण होते हैं और घने taxyksa dks viuh <ky dh rjg bLrseky djrs gSA rsyh; nkx uhfr ¼Oil Spot Policy) का उदाहरण देते हुए बताया है कि जिस प्रकार पानी की सतह पर तेल की बूंदें धीरे–धीरे फैलकर अपना आकार बढ़ाती हैं, उसी प्रकार विद्रोहियों ने विभिन्न राज्यों में अपना प्रसार किया।

मनोवैज्ञानिक युद्ध और दुष्प्रचार का तंत्र

नक्सलियों ने केवल हथियारों का ही नहीं, बल्कि सूचना और संस्कृति का भी प्रयोग किया।

सांस्कृतिक हथियारः स्थानीय आदिवासियों के साथ जुड़ने के लिए वे 'रेला' जैसे पारंपरिक नृत्यों और लोकगीतों का सहारा लेते हैं। भ्रामक प्रचारः 'नवभारत टाइम्स' (फरवरी 2026) के अनुसार, ''नक्सली संगठन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सरकारी योजनाओं को जन–विरोधी बताने का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं''। प्रशासनिक अवरोधः मानवाधिकार और आदिवासी अस्मिता के नाम पर सरकार को उलझाना उग्रवादियों की मुख्य कार्यविधि रही है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक नेटवर्क

भारतीय नक्सलवाद के तार वैश्विक स्तर पर सक्रिय प्रतिबंधित संगठनों से भी जुड़े रहे हैं।

वैश्विक संगोष्ठियांः वर्ष 1995 में बेल्जियम में आयोजित एक सेमिनार में 'पीपुल्स वार ग्रुप' ने भाग लिया था। CCOMPOSA: दक्षिण एशियाई माओवादी संगठनों ने मिलकर हथियारों और प्रशिक्षण के आदान–प्रदान के लिए एक एकीकृत मंच बनाया। विदेशी संगठनों से सहयोगः पेरू की 'लिबरेशन आर्मी' और 'कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी' जैसे संगठनों के साथ इनके वैचारिक संबंध देखे गए हैं।

सरकार की बहुआयामी जवाबी कार्रवाई

सरकार ने नक्सलवाद के विरुद्ध 'सुरक्षा और विकास' का एक समन्वित मॉडल अपनाया है। सैन्य अभियान, ऑपरेशन ग्रीन हंट छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में नक्सलियों के विरुद्ध एक

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i02.055

निर्णायक अभियान। ग्रेहाउंड्स (आंध्र प्रदेश): विशेष रूप से प्रशिक्षित इस बल ने हजारों नक्सलियों को निष्क्रिय करने में सफलता पाई। कोबरा (COBRA): सीआरपीएफ की इस विशेष इकाई को जंगलों में लड़ने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त है। विकासपरक पहल (योजना पत्रिका, 2024 संस्करण),रोशनी योजना, आदिवासी युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ना। आधारभूत संरचनाः डॉ. नीरज ने उल्लेख किया है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को जनता तक पहुँचाने से नक्सली प्रभाव कम हुआ है।

उग्रवाद का वैचारिक एवं सामरिक अवसानः एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन

भारतीय आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में नक्सलवाद का ह्रास केवल एक सामयिक घटना नहीं, अपितु एक सुव्यवस्थित राजकीय रणनीति और जन–आकांक्षाओं की विजय का प्रतीक है। इस पतन के विभिन्न आयामों का विस्तृत विवेचनात्मक विवरण निम्नवत हैः

1. वैचारिक विखंडन एवं सामाजिक आधार का क्षरणः जिस माओवादी दर्शन ने 'सशस्त्र क्रांति' के माध्यम से कृषकों और वंचितों को लामबंद किया था, वह आधुनिक विकासवादी चेतना के सम्मुख अप्रासंगिक हो गया है। 'दैनिक जागरण' (अक्टूबर 2025) के एक विश्लेषणात्मक लेख के अनुसार, ''नक्सलवाद का वैचारिक पतन उस क्षण सुनिश्चित हो गया जब उग्रवादियों ने अपने ही वर्ग के हितों के विरुद्ध हिंसक मार्ग का आश्रय लिया।''

2. प्रशासनिक सक्रियता एवं सुरक्षा बलों का वर्चस्वः 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' और 'ग्रेहाउंड्स' जैसे विशिष्ट बलों के निरंतर सैन्य दबाव ने नक्सलियों के रणनीतिक कौशल को पंगु बना दिया है 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' (फरवरी 2026) की एक रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि ''सुरक्षा बलों की सामरिक बढ़त और दुर्गम अंचलों में निरंतर गश्त ने नक्सलियों के सुरक्षित आश्रय स्थलों को उनके लिए कारागार में परिवर्तित कर दिया है।''

3. मुख्यधारा में प्रत्यावर्तन एवं नेतृत्व का संकटः शासन की उदार और मानवीय पुनर्वास नीतियों ने उग्रवादियों के कैडरों में वैचारिक परिवर्तन की लहर उत्पन्न की है, ''अमर उजाला'' (मार्च 2026) के सांख्यिकीय अध्ययन के अनुसार, ''विगत दो वर्षों में शस्त्र त्याग कर मुख्यधारा में सम्मिलित होने वाले विद्रोहियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे संगठन के भीतर द्वितीय पंक्ति के नेतृत्व का पूर्णतः लोप हो गया है।''

4. सूचना क्रांति एवं स्थानीय सहयोगः विगत कालखंड में स्थानीय आदिवासी समुदाय और सुरक्षा बलों के मध्य बढ़ती आत्मीयता ने नक्सलियों के 'सूचना तंत्र' को समूल नष्ट कर दिया है। अब ग्रामीण समाज उग्रवादियों को संरक्षण प्रदान करने के स्थान पर उनके विरुद्ध गुप्तचर सूचनाएँ शासन को उपलब्ध करा रहा है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' (मार्च 2026) के अनुसार, ''आदिवासी अंचलों में मोबाइल टावरों और इंटरनेट की पहुँच ने नक्सलियों के अलगाववादी प्रोपेगेंडा को पूर्णतः निष्प्रभावी कर दिया है।''

5. विकासात्मक परियोजनाओं का सकारात्मक प्रभावः 'रोशनी योजना' और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने उन क्षेत्रों में आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया है जहाँ कभी गरीबी को उग्रवाद का ईंधन बनाया जाता था। 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया' (PTI, जनवरी 2026) के एक समाचार

लेख के अनुसार, ''आर्थिक सशक्तिकरण ने युवाओं के मन से शस्त्रों के प्रति आकर्षण को समाप्त कर उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार बनाया है।''

स्थाई शांति की ओर बढ़ता भारतः सुरक्षा एवं विकास का स्वर्णिम संगम

नक्सलवाद के विरुद्ध भारत की वर्तमान सफलता केवल सैन्य शक्ति का प्रतिफल नहीं है, अपितु यह प्रशासनिक दूरदर्शिता और जन–केंद्रित नीतियों के सफल समन्वय का परिणाम है। इस वैचारिक और सशस्त्र संघर्ष के स्थाई समाधान हेतु अपनाए गए प्रयासों की विस्तृत विवेचना अधोलिखित हैः

लोकतांत्रिक मूल्यों का पुनरुत्थान और जन–चेतनाः आधुनिक भारत में 'बंदूक की सत्ता' के स्थान पर 'संवैधानिक शक्ति' ने अपनी सर्वोपरिता सिद्ध की है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' (मार्च 2026) की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में आदिवासी समाज उग्रवादियों के हिंसक तंत्र को पूर्णतः अस्वीकार कर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित होने हेतु अत्यधिक लालायित है। यह जन–परिवर्तन ही इस समस्या के स्थाई समाधान की प्रथम सीढ़ी सिद्ध हुआ है।

प्रशासनिक एवं सैन्य समन्वय की ऐतिहासिक विजयः 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' और केंद्रीय सुरक्षा बलों (CRPF) की निरंतर मुस्तैदी ने उग्रवादियों के सुरक्षित आश्रय स्थलों (Safe Havens) को समूल नष्ट कर दिया है। सुरक्षा बलों और स्थानीय गुप्तचर इकाइयों के मध्य बढ़ते गुणात्मक तालमेल ने नक्सलियों के सूचना तंत्र को आधारहीन बना दिया है। 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' (फरवरी 2026) के अनुसार, ''सुरक्षा बलों की सामरिक बढ़त ने नक्सली नेतृत्व को पूरी तरह से अलग–थलग कर दिया है।''

सर्वांगीण विकासः एक शाश्वत समाधानः सुदूर वन क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, विशुद्ध पेयजल और आजीविका के अवसरों की उपलब्धता ने उग्रवाद की वैचारिक जड़ों को शिथिल कर दिया है। 'द हिंदू' (संपादकीय, 12 मार्च 2021) ने यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि जब शासन की उपस्थिति समाज के अंतिम सोपान पर स्थित व्यक्ति तक पहुँचती है, तो अलगाववादी प्रवृत्तियों का स्वतः ही लोप हो जाता है।

कौशल विकास एवं आर्थिक स्वावलंबन की भूमिकाः 'रोशनी योजना' और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनवरत प्रयासों से प्रभावित जनपदों के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें गरिमामय रोजगार से जोड़ा गया है। 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया' (PTI, जनवरी 2026) के अनुसार, आर्थिक स्वावलंबन ने युवाओं को उग्रवाद के संकुचित एवं हिंसक मार्ग को त्यागकर राष्ट्र निर्माण की गौरवशाली दिशा में अग्रसर किया है।

प्रभावी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीतिः शासन द्वारा क्रियान्वित उदार एवं मानवीय पुनर्वास नीतियों ने उग्रवादियों को हिंसा त्यागने हेतु एक गरिमामय वैचारिक धरातल प्रदान किया है। 'अमर उजाला' (मार्च 2026) में प्रकाशित एक शोधपरक लेख के अनुसार, ''हथियार छोड़ मुख्यधारा में प्रत्यावर्तन करने वाले कैडरों की निरंतर बढ़ती संख्या ने नक्सली संगठनों के भीतर नेतृत्व का भीषण संकट उत्पन्न कर दिया है, जिससे उनका मनोबल पूरी तरह टूट चुका है।''

बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण और संचार क्रांतिः दुर्गम अंचलों में मोबाइल टावरों की स्थापना, सड़कों के जाल और सार्वजनिक सेवाओं के व्यापक विस्तार ने नक्सलियों के अलगाववादी प्रोपेगेंडा को विफल कर दिया है। यह सुदृढ़ अवसंरचना ही वर्तमान में स्थाई शांति की वास्तविक आधारशिला सिद्ध हो रही है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i02.055

अतीत बनती हिंसा और उज्ज्वल भविष्यः वर्तमान प्रवृत्तियों और 'द इकोनॉमिक टाइम्स' (फरवरी 2026) के विश्लेषणों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम और दुर्बलतम चरण में है। जनता के अभूतपूर्व सहयोग और प्रशासनिक सक्रियता के कारण यह हिंसक अध्याय अति शीघ्र केवल इतिहास के पन्नों तक ही सीमित रह जाएगा। निष्कर्षतः स्थाई शांति की यह यात्रा भारत के अटूट लोकतांत्रिक संकल्प की विजय है, जहाँ 'बुलेट' पर 'बैलेट' और 'विकास' की निर्णायक जीत हुई है।

निष्कर्ष (Detailed Conclusion)

प्रस्तुत शोध का गहन विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि नक्सलवाद का अस्तित्व उन्हीं क्षेत्रों में शेष रहा जहाँ राज्य की उपस्थिति और विकास की किरणें नहीं पहुँच पाई थी। मेरे द्वारा किए गए इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

1. वैचारिक पतनः नक्सलियों ने जिस 'बंदूक की सत्ता' का सपना देखा था, वह आधुनिक लोकतांत्रिक चेतना और जनता की प्रगतिशील आकांक्षाओं के सामने टिक नहीं सका।

2. प्रशासनिक एवं सैन्य समन्वयः 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' और केंद्रीय सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्यप्रणाली ने उग्रवादियों के सुरक्षित ठिकानों और उनके संचार तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है।

3. विकास ही स्थायी समाधानः डॉ. नीरज के विचारों का समर्थन करते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि जब शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल और रोजगार के अवसर समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचते हैं, तो नक्सलवाद जैसी समस्याएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं।

मुख्यधारा में वापसीः सरकार की आत्मसमर्पण और प्रभावी पुनर्वास नीतियों ने कई उग्रवादियों को हिंसा त्यागने के लिए प्रेरित किया है, जिससे संगठन के भीतर नेतृत्व का बड़ा संकट पैदा हो गया है। भावी संभावनाः वर्तमान प्रवृत्तियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में नक्सलवाद केवल एक ऐतिहासिक चर्चा और शोध का विषय बनकर रह जाएगा।

संदर्भ

1. जे.सी. जोहरी, नक्सलाइट पॉलिटिक्स इन इंडिया, रिसर्च पब्लिकेशन, 1972।
2. योजना पत्रिका, ''नक्सलवाद विशेषांक'', प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, मार्च 2006।
3. द हिंदू, ''नक्सलवाद का बदलता स्वरूप और प्रशासनिक चुनौतियां'', 12 मार्च 2021।
4. गृह मंत्रालय (MHA), वार्षिक रिपोर्टः ''भारत में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति'', भारत सरकार।
5. द इंडियन एक्सप्रेस, ''आदिवासी समाज और लोकतांत्रिक मूल्यों का पुनरुत्थान'', मार्च 2026।
6. अमर उजाला, ''हथियार छोड़ मुख्यधारा में प्रत्यावर्तनः एक अध्ययन'', मार्च 2026।
7. डॉ. नीरज, ''नक्सलवाद अपने अवसान की ओरः एक विश्लेषण'', शोध पत्र, राजकीय महिला महाविद्यालय, कुरावली, मैनपुरी।
8. विश्वजीत सपन, आतंकवाद एक परिचय, आकृति प्रकाशन, 2011।
9. पी.सी. जोशी, नक्सलिज्म एट ए ग्लांस, कल्पज प्रकाशन, 2012।
10. दृष्टि आईएएस, ''नक्सलवादः उदय, विस्तार एवं समाधान'', डिजिटल संसाधन।